

अध्याय 06: नवीन संवैधानिक विकास, न्यायिक निर्णय एवं संवैधानिक नैतिकता — शॉर्ट नोट्स

1. संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) — अर्थ, उत्पत्ति एवं विकास

अवधारणा / आयाम	संवैधानिक अर्थ, ऐतिहासिक उत्पत्ति एवं दार्शनिक आधार
संवैधानिक नैतिकता की परिभाषा	संविधान के मूल मूल्यों — स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, विधि का शासन, बहुलवाद तथा व्यक्ति की गरिमा के प्रति सर्वोच्च निष्ठा; भले ही यह समाज की प्रचलित पारंपरिक या बहुसंख्यक नैतिकता से टकराती हो
ऐतिहासिक उद्भव (George Grote)	19वीं सदी के ब्रिटिश इतिहासकार जॉर्ज ग्रोटे ने 'हिस्ट्री ऑफ ग्रीस' में इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया — संवैधानिक रूपों का पूर्ण आदर एवं सत्ता के अंगों में संयम
डॉ. बी.आर. अंबेडकर (1948)	4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में अंबेडकर ने कहा: 'संवैधानिक नैतिकता कोई प्राकृतिक सहज भावना नहीं है, इसे विकसित करना पड़ता है; हमारे देश की जनता को अभी इसे पूरी तरह सीखना बाकी है'
न्यायिक पुनर्जीवन	मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014) में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पुनः रेखांकित किया; 2018 के ऐतिहासिक फैसलों (नवतेज जौहर, सबरीमाला, जोसेफ शाइन) में यह न्यायपालिका का मुख्य आधार बना

तुलनात्मक आधार	संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality)	सार्वजनिक / बहुसंख्यक नैतिकता (Popular Morality)
स्रोतों का आधार	संविधान के मूल दर्शन, प्रस्तावना, मूल अधिकार (Part III) एवं मानवीय गरिमा पर आधारित	समाज की स्थापित परंपराओं, रूढ़ियों, धर्म, मान्यताओं तथा बहुसंख्यक वर्ग की प्राथमिकताओं पर आधारित
परिवर्तनशीलता	प्रगतिशील, जीवंत और मानवीय अधिकारों का विस्तार करने वाली (Living Tree Model)	प्रायः यथास्थितिवादी, रूढ़िवादी तथा सामाजिक पूर्वाग्रहों से प्रभावित
टकराव की स्थिति में	संवैधानिक नैतिकता सदैव सर्वोच्च होगी; न्यायालय जनमत या बहुसंख्यक भावना के दबाव में नहीं आ सकता	बहुसंख्यक भावना को संविधान के मूलभूत अधिकारों (अनु. 14, 15, 21) पर थोपा नहीं जा सकता
न्यायिक अधिदेश	न्यायालय का कर्तव्य बहुसंख्यक समाज को खुश करना नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक व हाशिए के वर्गों की गरिमा की रक्षा करना है	केवल जनभावना का आदर करती है, जो समय-समय पर मनमानी और असहिष्णु हो सकती है

2. संवैधानिक नैतिकता के 4 आधार स्तंभ एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन

स्तंभ / आलोचना	संवैधानिक सिद्धांत एवं विधिक सीमाएं
1. विधि का शासन (Rule of Law)	कानून के समक्ष सभी समान; सत्ता का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं, स्थापित विधिक नियमों के अनुसार ही संभव
2. व्यक्तिगत स्वतंत्रता व गरिमा	व्यक्ति स्वयं में एक साथ (End) है, साधन नहीं; प्रत्येक नागरिक की गरिमा व स्वायत्तता अनुल्लंघनीय है
3. संस्थागत संयम व संतुलन	संविधान के तीनों अंगों (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) द्वारा अपनी संवैधानिक सीमाओं का स्वेच्छा से पालन
आलोचना: न्यायिक व्यक्तिपरकता	संवैधानिक नैतिकता की कोई स्पष्ट वैधानिक परिभाषा न होने से न्यायाधीशों के व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों (Subjectivity) का खतरा
आलोचना: शक्ति पृथक्करण उल्लंघन	विधायिका के नीतिगत अधिकारों में न्यायपालिका का अनुचित हस्तक्षेप; 'न्यायिक कानून-निर्माण (Judicial Legislation)' की आशंका

3. ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय (2017-2019) — संवैधानिक मूल्यों का विस्तार

ऐतिहासिक वाद / वर्ष	पीठ / अनुच्छेद	संवैधानिक मुद्दे, ऐतिहासिक निर्णय एवं विधिक प्रभाव
के.एस. पुट्टास्वामी वाद (2017)	9 जज संविधान पीठ [अनु. 21]	निजता का अधिकार (Right to Privacy) अनुच्छेद 21 के तहत अंतर्निहित मूल अधिकार घोषित; खड़क सिंह (1962) व एम.पी. शर्मा (1954) के संकीर्ण निर्णय निरस्त; 3-स्तरीय परीक्षण (Legality, Need, Proportionality)
नवतेज सिंह जौहर वाद (2018)	5 जज पीठ [अनु. 14, 15, 19, 21]	आईपीसी की धारा 377 का वह अंश असंवैधानिक घोषित जो वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध मानता था; सुरेश कुमार कौशल (2013) निर्णय निरस्त; संवैधानिक नैतिकता को सामाजिक नैतिकता पर वरीयता
शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017)	5 जज पीठ [अनु. 14, 21, 25]	मुस्लिम समाज में प्रचलित 'तीन तलाक' (Talaq-e-Biddat) को 3:2 बहुमत से असंवैधानिक व शून्य घोषित; इसे मनमाना व समानता-विरोधी माना; संसद द्वारा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 पारित
सबरीमाला मंदिर वाद (2018)	5 जज पीठ (4:1) [अनु. 14, 25]	केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर लग प्रतिबंध निरस्त; मासिक धर्म के आधार पर भेदभाव अस्पृश्यता (अनु. 17) का ही एक रूप; भक्ति व ईश्वर पूजा में लिंग-आधारित विभेद वर्जित
जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018)	5 जज पीठ [अनु. 14, 15, 21]	आईपीसी की धारा 497 (व्यभिचार / Adultery) को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित; महिला को पति की संपत्ति मानने वाली औपनिवेशिक धारणा समाप्त; व्यभिचार अब अपराध नहीं, केवल तलाक का दीवानी आधार

ऐतिहासिक वाद / वर्ष	पीठ / अनुच्छेद	संवैधानिक मुद्दे, ऐतिहासिक निर्णय एवं विधिक प्रभाव
अयोध्या भूमि विवाद वाद (2019)	5 जज सर्वसम्मत पीठ [अनु. 142]	2.77 एकड़ विवादित भूमि का स्वामित्व रामलला विराजमान (ट्रस्ट) को सौंपा; मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण हेतु 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि आवंटित; अनुच्छेद 142 के तहत 'पूर्ण न्याय' की शक्ति का प्रयोग

4. नवीनतम संवैधानिक निर्णय (2020-2025) — समसामयिक विधिक परिदृश्य

नवीनतम न्यायिक वाद / वर्ष	पीठ / अनुच्छेद	संवैधानिक प्रावधान, न्यायालय का निर्णय एवं नीतिगत प्रभाव
अनुच्छेद 370 निरसन वाद (2023)	5 जज सर्वसम्मत पीठ [अनु. 370, 356]	5 अगस्त 2019 के संवैधानिक आदेश (CO 272 व 273) को वैध ठहराया; अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था; जम्मू-कश्मीर राज्य के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी; लद्दाख को UT बनाना वैध; राज्य का दर्जा शीघ्र बहाल करने का निर्देश
चुनावी बॉन्ड वाद (ADR 2024)	5 जज सर्वसम्मत पीठ [अनु. 19(1)(a)]	इलेक्टोरल बॉन्ड योजना (2018) पूर्णतः असंवैधानिक घोषित; कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को असीमित व गुप्त चंदा देना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मतदाताओं के 'जानने के अधिकार' का सीधा उल्लंघन; भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को समस्त विवरण सार्वजनिक करने का आदेश
समलैंगिक विवाह वाद (2023)	5 जज पीठ (सुप्रियो वाद) [अनु. 21]	3:2 बहुमत से निर्णय: समलैंगिक व्यक्तियों को विवाह करने का कोई मूल अधिकार या विशेष विवाह अधिनियम के तहत विधिक मान्यता नहीं; विवाह को मान्यता देने का अधिकार केवल विधायिका (संसद) का है; न्यायालय ने न्यायिक संयम (Judicial Restraint) दिखाया
राज्यपाल विधेयक शक्ति वाद (2023-24)	3 जज पीठ [अनुच्छेद 200]	पंजाब व तमिलनाडु राज्य संदर्भ: राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चितकाल के लिए दबाकर नहीं बैठ सकते; यदि राज्यपाल सहमति रोकते हैं, तो उन्हें विधेयक को 'यथाशीघ्र' पुनर्विचार हेतु सदन को लौटाना होगा; राज्यपाल निर्वाचित सरकार के समानांतर शक्ति केंद्र नहीं
SC/ST कोटा उप-वर्गीकरण वाद (2024)	7 जज संविधान पीठ (6:1) [अनु. 341, 16(4)]	ई.वी. चिन्नैया (2004) निर्णय निरस्त; राज्यों को अनुसूचित जातियों (SC) एवं अनुसूचित जनजातियों (ST) के भीतर सबसे पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता देने हेतु उप-वर्गीकरण (Sub-classification) करने का अधिकार; क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने की संस्तुति

5. न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक अतिरेक — तुलना

तुलनात्मक आयाम	न्यायिक समीक्षा (Review)	न्यायिक सक्रियता (Activism)	न्यायिक अतिरेक (Overreach)
संवैधानिक स्थिति	संविधान का आधारभूत ढांचा (अनु. 13, 32, 226); स्पष्ट विधिक प्राधिकार	न्यायिक नवाचार (1980 के दशक से जनहित याचिका (PIL) द्वारा विकसित); संविधान-सम्मत	असंवैधानिक; शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का खुला उल्लंघन
प्रकृति व दृष्टिकोण	विधायिका/कार्यपालिका के कानूनों की संवैधानिकता की निष्पक्ष जांच	नागरिक अधिकारों की रक्षा व कार्यपालिका की निष्क्रियता दूर करने हेतु सक्रिय हस्तक्षेप	न्यायपालिका द्वारा स्वयं कार्यपालिका या विधायिका की भूमिका अपना लेना
प्रमुख उदाहरण	99वें संशोधन (NJAC) व चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करना	विशाखा दिशानिर्देश (1997), कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, स्वच्छ पर्यावरण निर्देश	हाईवे पर शराब बिक्री प्रतिबंध, सिनेमाघरों में राष्ट्रगान अनिवार्य करना, पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध

6. जनहित याचिका (PIL) — उद्भव, विशेषताएं, लाभ एवं दुरुपयोग नियंत्रण

जनहित याचिका (PIL) के प्रमुख आयाम	संवैधानिक पृष्ठभूमि, विधिक प्रक्रिया एवं न्यायिक दिशानिर्देश
उद्भव एवं जनक	1980 के दशक में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती एवं न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर द्वारा सूत्रपात; अमेरिकी न्यायशास्त्र से प्रेरित
पारंपरिक नियम में छूट	पारंपरिक 'लोकस स्टैंडार्ड' (Locus Standi — वाद का अधिकार) के नियम में ढील — कोई भी नागरिक या संस्था निर्धन व वंचित वर्गों के अधिकारों हेतु न्यायालय जा सकती है
प्रमुख ऐतिहासिक जनहित याचिकाएं (PIL)	हुस्नआरा खातून (1979 — विचाराधीन कैदी), एस.पी. गुप्ता (1981 — जजों की नियुक्ति), विशाखा वाद (1997 — महिला सुरक्षा), एम.सी. मेहता (गंगा प्रदूषण, ताजमहल संरक्षण)
दुरुपयोग की रोकथाम दिशानिर्देश	बलवंत सिंह चौटालिया वाद (2010): सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी व प्रचार-लोलुप याचिकाओं पर रोक हेतु 8 दिशानिर्देश जारी किए — याचिकाकर्ता की साख जांच, भारी जुर्माना व वास्तविक जनहित की पुष्टि अनिवार्य

7. प्रमुख संवैधानिक सिद्धांतों एवं ऐतिहासिक वादों की त्वरित संदर्भ तालिका

प्रमुख संवैधानिक सिद्धांत	निर्णायक ऐतिहासिक वाद	संवैधानिक प्रभाव एवं सार
संवैधानिक नैतिकता	नवतेज जौहर (2018), सबरीमाला (2018)	सामाजिक रूढ़िवादिता पर संवैधानिक मूल्यों की सर्वोच्चता
निजता का मूल अधिकार	के.एस. पुट्टास्वामी वाद (2017)	अनुच्छेद 21 के तहत अंतर्निहित, अविभाज्य मूल अधिकार

प्रमुख संवैधानिक सिद्धांत	निर्णायक ऐतिहासिक वाद	संवैधानिक प्रभाव एवं सार
समानता व लैंगिक न्याय	शायरा बानो (2017), जोसेफ शाइन (2018)	मनमाने धार्मिक नियमों व पितृसत्तात्मक कानूनों का उन्मूलन
मतदाताओं का सूचना अधिकार	चुनावी बॉन्ड वाद (ADR 2024)	अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत राजनीतिक वित्तपोषण में पूर्ण पारदर्शिता
विधायिका की सर्वोच्चता में संयम	सुप्रियो बनाम भारत संघ (2023)	विवाह अधिकार मान्यता में नीतिगत संयम; संसद का अनन्य अधिकार

7. प्रमुख संवैधानिक सिद्धांत (क्रमशः)

प्रमुख संवैधानिक सिद्धांत	निर्णायक ऐतिहासिक वाद	संवैधानिक प्रभाव एवं सार
संघात्मक संतुलन	राज्यपाल विधेयक शक्ति वाद (2023-24)	अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा विधानसभा की उपेक्षा असंवैधानिक
आरक्षण में उप-वर्गीकरण	कोटा उप-वर्गीकरण वाद (2024)	(SC/ST) में सर्वाधिक पिछड़े वर्गों हेतु अलग आरक्षण कोटा वैध

न्यायिक भूमिका का मूल निष्कर्ष: न्यायपालिका को 'संविधान का संरक्षक (Protector of the Constitution)' रहना चाहिए, 'संविधान का शासक (Ruler of the Constitution)' नहीं। संवैधानिक नैतिकता, न्यायिक सक्रियता एवं शक्ति पृथक्करण का संतुलन ही भारतीय लोकतंत्र की सुदृढ़ता का स्थायी आधार है।